



**30 महीने**  
**30 उपलब्धियां**  
**नये कदम**  
**बढ़ते कदम**



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

## प्रधानमंत्री जी ने किया एलान नये साल पर नई सौगात

- रबी की बुआई के लिए सहकारी बैंक एवं प्राइमरी सोसायटी से लिए गये कर्ज का 60 दिन का ब्याज भारत सरकार वहन करेगी।
- को-ओपरेटिव बैंक और सोसायटी से आसान कर्ज हेतु नाबार्ड ने 21,000 करोड़ की व्यवस्था की थी। अब भारत सरकार ने इसे लगभग दोगुना करते हुए 41,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
- अगले तीन महीने में तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को रुपये क्रेडिट कार्ड में बदला जाएगा जिससे किसानों को पैसा निकालने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा।
- Government to pay interest for 60 days for the loan taken by farmers for Rabi season from district cooperative banks and primary societies.
- NABARD credited fund of Rs. 21,000 crore for better access to loans from cooperative banks & societies. Now government has approximately doubled it to Rs. 41,000 crore.
- The government has decided that three crore farmers who have Kisan Credit Cards, will be given Rupay debit cards within three months so that they don't have to go to banks to withdraw money.



**कुशल नेतृत्व**

**सफल प्रयास**

**तीव्र विकास**

# व्यक्तिगत जानकारी

नाम .....

कार्यालय पता .....

.....

दूरभाष ..... ई-मेल .....

मोबाइल नं. .... फ़ैक्स नं. ....

आवासीय पता .....

.....

दूरभाष..... रुधिर-वर्ग .....

कद ..... वज़न..... दिनांक.....

कार / मोटर साईकिल संख्या.....

ड्राइविंग लाइसेंस संख्या.....

## महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र

चिकित्सक..... बैंक प्रबंधक .....

बीमा अभिकर्ता..... यात्रा अभिकर्ता.....



श्री राधा मोहन सिंह  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री



श्री एस.एस. अहलुवालिया  
कृषि एवं किसान कल्याण  
और संसदीय कार्य राज्यमंत्री



श्री परशोत्तम रूपाला  
कृषि एवं किसान कल्याण  
राज्यमंत्री



श्री सुदर्शन भगत  
कृषि एवं किसान कल्याण  
राज्यमंत्री

स्वस्थ धरा, खेत हरा

## **1. PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA**

About 309 lakh farmers of 23 states had been covered under Fasal Beema during previous Kharif Season 2015 in which 294 lakh farmers were lonee and 15 lakh farmers were non-lonee. During Kharif 2016, however, 374 lakh farmers have been covered out of which 271 lakh farmers are lonee and 103 lakh farmers are non-lonee. Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana has been implemented by 21 states during Kharif 2016.

## **2. SOIL HEALTH CARD SCHEME**

Against a target of 2.53 crore soil samples collection upto March 2017, 2.33 crore soil samples have been collected till 27.12.2016, from which 12.82 crore soil health cards are being made. Out of these, 4.31 crore soil health cards have printed and 4.25 crore soil health cards have been distributed to the farmers and remainings are under process. During 2016-17, 0.20 crore samples are to be collected from which 1.10 crore soil health cards will be prepared. Before 2014 only 15 Soil Testing Laboratories were sanctioned while in 2014-16, 460 Soil Testing Labs and 4000 mini labs have been sanctioned to the States.

## 1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

इस योजना के तहत खरीफ 2015–16 में 309 लाख (294 लाख ऋणी व 15 लाख गैर ऋणी) किसानों ने बीमा कराया जबकि 2016–17 के खरीफ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 374 लाख (271 लाख ऋणी व 103 लाख गैर ऋणी) किसानों ने बीमा कराया।

## 2. स्वायल हैल्थ कार्ड

इस योजना के तहत मार्च 2017 तक 2.53 करोड़ स्वायल नमूना संग्रहण के लक्ष्य के सापेक्ष 27–12–2016 तक 2.33 करोड़ संग्रहित किये जा चुके हैं, जिनसे 12.82 करोड़ कार्ड बनाए जा रहे हैं। अभी तक 4.25 करोड़ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। 2014 से पहले केवल 15 प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई थी जबकि 2014–16 के दौरान 460 प्रयोगशालाएं एवं 4000 मिनी लैब भी राज्यों को स्वीकृत किए गए।

### **3. PARAMPARAGAT KRISHI VIKAS YOJANA**

The scheme was started in 2015 to promote organic farming with an allocation of Rs. 597 crore for three years and a target to set up 10,000 clusters. Till December, 2016, State Governments have made 9186 clusters.

### **4. NATIONAL AGRICULTURE MARKET (NAM)**

Under this scheme, 250 mandis of 10 states have been integrated with e-NAM Portal. In principal approval has been to integrate 399 mandis with e-NAM for which an amount of Rs. 83 crore has been released. As on 27.12.2016, 35,04,371.13 tonnes of agriculture produce worth Rs. 7,131.21 crore has been transacted on e-NAM platform. As on 27.12.2016, 9,49,112 Farmers, 59,742 Traders and 31,317 Commission Agents have been registered on the e-NAM platform.

### **5. PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA (PMKSY)**

During 2013-14, an area of 4.3 lakh hectare was covered under micro irrigation. Whereas, during 2014-16, an area of 12.74 lakh hectare has been brought under micro irrigation under Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana which is an increase of 200 %. PMKSY scheme is being implemented in



### 3. परंपरागत कृषि विकास योजना

इस योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015 से तीन वर्षों के लिए 597 करोड़ रु आवंटित किए गये जिनसे 10,000 क्लस्टर बनाए जाने थे। दिसम्बर, 2016 तक 9186 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं।

### 4. राष्ट्रीय कृषि बाजार

इस योजना के तहत 10 राज्यों की 250 मंडियों को सितंबर 2016 तक ई नाम पोर्टल से जोड़ दिया गया है व 399 मंडियों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसके लिए 83 करोड़ रुपये निर्गत किये जा चुके हैं। 27.12.2016 तक 7,131.21 करोड़ रुपये के 35,04,371.13 टन कृषि उत्पाद का कारोबार e&NAM पर हो चुका है। 27.12.2016 तक 9,49,112 किसानों, 59,472 व्यापारियों और 31,317 कमीशन एजेंटों को e&NAM प्लेटफार्म पर पंजीकृत किया जा चुका है।

### 5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 2013-14 में 4.3 लाख हैक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया गया जबकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2014-16 में 12.74 लाख हैक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई के अधीन लाया गया है जो की 200 प्रतिशत की वृद्धि

mission mode with aim of completing 99 major and medium irrigation projects with the capacity of 76.03 lakh hectare in a phased manner by December, 2019 with command area development with an amount of Rs. 77,595 crore. During the year 2016-17, a sum of Rs. 12,517 crore will be incurred to implement 23 irrigation schemes under PMKSY Mission.

## **6. DEVELOPMENT OF BEEKEEPING**

Honey production has increased from 1,48,450 MT during 2012-14 to 2,63,930 MT during 2014-16 (up to December, 2016) which is an increase of 78 %. An amount of Rs. 19.15 crores released to National Bee Board (NBB) during last two years (2014-16) in comparison to an amount of Rs. 5.94 crores released during last three years (2011-12 to 2013-14).

हैं। पीएमकेएसवाई स्कीम को कमान क्षेत्र विकास सहित दिसम्बर 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 76.03 लाख हैक्टेयर की क्षमता के साथ 99 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है जो रु. 77,595 करोड़ की लागत से पूरा होगा। वर्ष 2016-17 के लिए रु.12,517 करोड़ के माध्यम से 23 योजनाएं पूरी की जाएंगी।

## 6. मधुमक्खी विकास

मधुमक्खी विकास के तहत 2012-14 में 1,48,450 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जबकि 2014-16 (दिसम्बर 2016 तक) में 2,63,930 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ जो कि 78 प्रतिशत की वृद्धि है। नेशनल बी बोर्ड (एन बी बी) को मधुमक्खीपालन विकास के लिए पिछले तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) में कुल रुपये 5.94 करोड़ की वित्तीय सहायता के एवज में पिछले दो वर्षों (2014-16) में कुल रुपये 19.15 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गयी।

## **7. FARMER PRODUCER ORGANIZATION (FPO)**

568 FPOs have been registered during 2014-16 (2 Years) while 223 FPOs were registered during 2011-14 (3 years) which is an increase of 155 %.

## **8. FINANCING OF JOINT LIABILITY GROUPS (JLGS)**

Financing of 18.21 lakh Joint Liability Groups from 2014 to 2016 during just 2 ½ years as compared to 6.7 lakh JLGs during the 7 years from 2007 to 2014. In comparison to cumulative achievement of Rs. 6630 cr. During 7 years from 2007 to 2014, Rs. 18,005.79 cr. Were made available to JLGs during just 2 ½ years from 2014 and September, 2016.

## **9. HORTICULTURE**

During last decade area under horticulture has increased about 2.7% per year and annual production has increased by 5.5%. In spite of two successive droughts during 2014-15 and 2015-16, the production of horticulture crops has increased.

## 7. एफपीओ

एफपीओ के तहत 2011–14 के दौरान (3 वर्षों में) 223 एफपीओ का पंजीकरण हुआ जबकि 2014–16 के दौरान (2 वर्षों में) 568 एफपीओ का पंजीकरण हुआ जो कि 155 प्रतिशत की वृद्धि है।

## 8. ज्वाइंट लाएबिलिटी ग्रुप को वित्तीय सहायता

2007 से 2014 तक (7 वर्षों में) 6.7 लाख ज्वाइंट लाएबिलिटी समूहों की तुलना में 2014 से 2016 (2.5 वर्षों में) 18.21 लाख समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। 2007 से 2014 तक (7 वर्षों में) रु. 6630 करोड़ की संचित उपलब्धियों की तुलना में 2014 से सितम्बर 2016 (2.5 वर्षों) तक रु. 18,006 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता संयुक्त देय समूहों को प्रदान की गयी।

## 9. बागवानी

पिछले दशक में बागवानी के तहत क्षेत्र प्रति वर्ष लगभग 2.7 प्रतिशत बढ़ा है और वार्षिक उत्पादन 5.5 प्रतिशत बढ़ा है। लगातार दो वर्ष 2014–15 व 2015–16 में सूखा पड़ने के बावजूद, बागवानी के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

## **10. COCONUT DEVELOPMENT**

From the beginning of this financial year 2016-17, India has started exporting Coconut Oil to Malaysia, Indonesia and Sri Lanka from where coconut oil was being imported from these countries in previous years. India became first in coconut production and productivity in the world. Coconut area, production and productivity reached 1.97 million ha, 20.439 billion nuts and 10345 nuts per ha respectively. 33% increase found in replanting and area rejuvenation of Coconut Development Board (CDB) during the year 2014-16 as compared to 2011-14.

## **11. STATE DISASTER RELIEF FUND**

For the years 2010-2015, a provision of Rs. 33580.93 crore was made for State Disaster Response Fund. The same has been increased to Rs. 61,220 crore for the period 2015-2020.

## **12. NATIONAL DISASTER RELIEF FUND**

During 2010-14, States sought an assistance of Rs. 92,044 cr. and were granted Rs. 12,516 cr. Whereas during, 2014-16, States sought an assistance of Rs. 94,787 cr. and were granted Rs. 24,556 cr.

## 10. नारियल विकास

इस वित्तीय वर्ष 2016–17 की शुरुआत से ही भारत नारियल तेल का निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को करने लगा है। जबकि हम पिछले वर्ष तक इन्हीं देशों से नारियल तेल का आयात कर रहे थे। दुनिया में भारत नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। नारियल क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में क्रमशः 1.97 करोड़ हेक्टेयर, 20,439 बिलियन नट और 10,345 नट प्रति हेक्टेयर है। साथ ही नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) के पुनर्रोपण और क्षेत्र की कार्यकलापो में 2011–14 की तुलना में वर्ष 2014–16 के दौरान 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

## 11. राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (SDRF)

राज्यों को 2010–15 के दौरान राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (SDRF) में रु. 33581 करोड़ निर्गत किये गये जबकि 2015–20 के दौरान रु. 61219 करोड़ आवंटित किए गये हैं।

## 12. राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (SDRF)

राज्यों ने 2010–14 के दौरान राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (SDRF) से रु. 92,044 करोड़ मांगे जिसके सापेक्ष रु. 12,516 करोड़ स्वीकृत किए गये। जबकि राज्यों ने 2014–16 के दौरान रु. 94,787 करोड़ मांगे जिसके सापेक्ष रु. 24,556 करोड़ स्वीकृत किए गये।

### **13. NEEM COATED UREA**

In one year, Modi Government has made available 100% neem coated area in the country. Due to this diversion of unauthorized use of urea by Chemical Factories has been stopped. Now farmers are getting urea in adequate quantity. Besides this, the cost of production is being reduced by 10-15% with the use of neem coated urea. Productivity will also increase with the use of Neem Coated Urea.

### **14. AGROFORESTRY**

For the first time, “Sub-Mission on Agroforestry” has been initiated which will accelerate the programme “Medh Par Ped”. In addition, trees would also be grown as strip and intermittent plantation on farm land along with crops/ cropping system and as block plantation in cultivable waste land. Implementation of the scheme only in the states having liberalized transit regulations for transport of timber and will be extended to other states as and when such relaxations are notified by them. So far, the scheme is being implemented in 8 states.



### 13. नीम कोटेड यूरिया

मोदी सरकार ने एक वर्ष में पूरे देश में अब नीम कोटेड यूरिया 100 प्रतिशत उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इससे यूरिया का अवैध रूप से रसायन उद्योग में दुरुपयोग समाप्त हो गया है। अब किसानों को यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। नीम लेपित यूरिया के उपयोग से उत्पादन लागत में 10-15 प्रतिशत की भी कमी हो रही है। इसके उपयोग से उत्पादकता भी बढ़ेगी।

### 14. कृषि वानिकी

हर खेत के मेड़ पर पेड़, परती भूमि पर पेड़ तथा inter cropping में पेड़ लगाने के उद्देश्य से पहली बार “कृषि वानिकी उप-मिशन” क्रियान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत “मेड़ पर पेड़” अभियान को गति मिलेगी। इसके अलावा खेत में फसलों / फसल तंत्र के साथ पट्टी, अंतरायिक रूप में पेड़ एवं ब्लॉक प्लांटेशन लगाए जाने का प्रावधान है। खेती योग्य बंजर भूमि में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। स्कीम का कार्यान्वयन उन्हीं राज्यों में किया जायेगा जिसमें इमारती लकड़ी के परिवहन हेतु उदारीकृत परिवहन विनियमन हो और अन्य राज्यों में तभी लागू की जायेगी जब उनके द्वारा छूट अधिसूचित की जाती है। अभी तक 8 राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है।

## **15. Coordinated programme on Horticulture Assessment and Management using geo-Informatics (CHAMAN)**

The programme has the objective to develop and firm up methodology for estimation of area and production under horticulture crops using “Remote Sensing Technology” and “Sample Survey Methodology”. Launched during September, 2014; to be completed in 3 years.

## **16. INITIATION OF MOBILE APP FOR FARMERS**

Following mobile apps have been launched for the welfare of farmers: Kisan Suvidha, PUSA Agriculture, Agri Market, Crop Insurance and Crop Cutting Experiment (CCE) which can be downloaded from google play store as well as from [www.mkisan.gov.in](http://www.mkisan.gov.in)

## **17. NATIONAL FOOD SECURITY MISSION (NFSM) / STEPS TAKEN FOR PULSE PRODUCTION**

- Till 2013-14 only three crops were covered under National Food Security Mission namely – Rice, Wheat & Pulses. The coverage during Modi Government has been increased to seven crops namely – Rice, Wheat, Pulses, Jute, Sugarcane, Cotton & Coarse Cereals.

## 15. चमन परियोजना: बागवानी आकलन और प्रबंधन जियोइन्फारमैटिक्स के प्रयोग पर समन्वित कार्यक्रम (चमन)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य "रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी" और "नमूना सर्वेक्षण पद्धति" का उपयोग कर बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के आकलन के लिए कार्यप्रणाली को विकसित और मज़बूत करना है। सितंबर, 2014 के दौरान शुरू; 3 साल में पूरा किया जाना है।

## 16. किसानों के लिए मोबाइल एप की शुरुआत

किसानों की सुविधा के लिए मोबाइल एप: किसान सुविधा, पूसा कृषि, एग्री मार्केट, फसल बीमा और फसल कटाई प्रयोग शुरू की गई है जो [www.mkisan.gov.in](http://www.mkisan.gov.in) के अलावा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

## 17. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) / दलहन उत्पादन के लिए उठाए गए कदम

- वर्ष 2013–14 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत केवल तीन फसलें – चावल, गेहूँ, दलहन शामिल थी। मोदी सरकार द्वारा इस मिशन के अंतर्गत सात फसलें— चावल, गेहूँ, दलहन, जूट, गन्ना, कपास व मोटे अनाज शामिल किये जा चुके हैं।

- Till the year 2013-14, 482 districts of 16 States were included in National Food Security Mission (NFSM). Now with the addition 8 North Eastern States, 3 Hilly States (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand), Goa and Kerala, the Mission covers all 638 districts of 29 States in the country.
- Out of the total allocation of Rs.1700 crores under NFSM for 2016-17, Rs.1,100 crore (central share) was allocated for pulses which amounts to more than 60% of total allocation.
- For expansion of cultivation of new kinds of seeds, Rs.7.85 lakhs mini-kits are being distributed to farmers free of cost in the year 2016-17, through State Governments.
- In the year 2016-17, demonstrations of new techniques for pulse production are being carried out in 31,000 hectares by 534 Agriculture Science Centers through ICAR & State Agriculture Universities and Rs.25.29 crores were allocated for this purpose.
- Seed Hubs are being created through ICAR, State Agriculture Universities and Krishi Vigyan Kendras (KVKs) for ensuring the availability of new kinds of seeds. For this purpose, Rs. 225.31 crore have been approved for establishment of

- वर्ष 2013–14 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन में 16 राज्यों के 482 जिलें शामिल थे जो अब 8 उत्तर पूर्वी राज्यों, 3 पहाड़ी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड) तथा गोवा एवं केरल को शामिल करते हुए वर्ष 2016–17 में दलहन के तहत देश 29 राज्यों के सभी 638 जिले सम्मिलित है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए वर्ष 2016–17 के कुल आवंटन रू.1,700 करोड़ में से दलहनों के लिए रू. 1,100 करोड़ (केंद्रांश) आवंटित किए गए जो कुल आवंटन का 60 प्रतिशत से अधिक है।
- नई किस्मों के बीजों के प्रसार के लिए 7.85 लाख दलहन मिनिकिट राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को वर्ष 2016–17 में मुफ्त वितरण किया जा रहा है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से दालों के लिए 534 कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा 31000 हेक्टर में नई तकनीकों के प्रदर्शन 2016–17 में किए जा रहे हैं, जिसके लिए 25.29 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।
- नए किस्मों के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर बीज हब का सृजन किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2016–17 से 2017–18 के दौरान रू. 225.31 करोड़ के साथ 150 बीज केन्द्रों

150 seed centers during 2016-17 to 2017-18, out of which Rs.131.74 crore is proposed for 2016-17. From these seed centers 1.50 lakh quintals of improved seeds will be ensured.

- The production target for pulses for the year 2016-17 is 20.75 million metric tonnes. The production of kharif pulses in 2016-17 is expected about 8.70 million tonnes (as per 1st Advance Estimates) against target of 7.25 million tonnes

## **18. RASHTRIYA GOKUL MISSION**

With a view to conserve and develop indigenous bovine breeds, Rashtriya Gokul Mission, a new initiative under National Programme for Bovine Breeding and Dairy Development has been launched for the first time in the country, with an allocation of Rs 500 crore. Under the Mission, 14 Gokul Grams are being established, 35 Bull Mother Farms modernized with investment of more funds and 3629 Bulls have been inducted for genetic upgradation. Since 2007-08 to 2013-14, a meagre amount of only Rs 45 crore was spent for the development of indigenous breeds. Whereas, the current Government has in only one and a half years, upto December 2015, has approved

की स्थापना का अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें रु. 131.74 करोड़ 2016–17 के लिए प्रस्तावित है। इससे कुल 1.50 लाख क्विंटल उन्नत बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

- फलस्वरूप, वर्ष 2016–17 के लिए दालों का उत्पादन लक्ष्य 20.75 मिलियन मेट्रिक टन है। वर्ष 2016–17 में खरीफ दालों के 7.25 मिलियन टन के उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 8.70 मिलियन टन (प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार) होने की आशा है।

## 18. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' की 500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है तथा सांडों के उन्नयन हेतु 35 पशु प्रक्षेत्र को अधिक धन देकर आधुनिक बनाया गया है। इसके साथ 3,629 सांडों को आनुवांशिक उन्नयन हेतु आवंटित कर दिया गया है। देसी नस्लों के विकास के लिए 2007–08 से 2013–14 तक केवल रु. 45 करोड़ इस कार्य के लिए खर्च किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा दिसंबर 2015 तक केवल डेढ़ वर्षों में 27 राज्यों से आए 35 प्रस्तावों के लिए रु. 582.09 करोड़

35 projects from 27 States and has sanctioned Rs 582.09 crore. This amount has been increased by more than 13 times in the last two years. Two National Kamdhenu Breeding Centre, one in northern region-Madhya Pradesh and other in Southern region- Andhra Pradesh, are being established in the country with an allocation of Rs 50 crores.

## **19. MILK PRODUCTION**

Against 1370 lakh ton milk produced during 2012-14, 1550 lakh ton was produced during 2014-16, an increase of 11.7 %. During 2015-16 annual milk production registered an increase of 6.3 %.

## **20. FOUR NEW SCHEMES FOR DAIRY SECTOR**

### **a) PASHUDHAN SANJIVANI**

- An animal Wellness Programme; encompassing provision of Animal Health cards ('Nakul Swasthya Patra') along with UID identification of animals in milk and a National Data Base.
- Under the scheme 8.5 crore animals in milk will be identified using UID and their data will be uploaded in the INAPH data base.
- This will play a crucial role in the control of spread of animal diseases. This will also lead to an increase in trade of livestock and livestock products.



स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह धन पिछले दो वर्षों के दौरान 13 गुणा बढ़ा दिया गया है। दो नए राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर (एक उत्तर भारत-मध्य प्रदेश और एक दक्षिण भारत- आंध्र प्रदेश में) भी स्थापित किए जा रहे हैं जिसके लिए रु. 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

## 19. दूध उत्पादन

वर्ष 2012-14 के दौरान 1370 लाख टन का उत्पादन हुआ जबकि 2014-16 के दौरान 1550 लाख टन का उत्पादन हुआ जोकि 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है। 2015-16 में दुग्ध उत्पादन में 6.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।

## 20. डेयरी के लिए अलग से चार नई परियोजनाएं प्रारम्भ

### (ए) पशुधन संजीवनी-नकुल स्वास्थ्य पत्र

- यह एक पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा जिसके तहत पशु स्वास्थ्य पत्र (नकुल स्वास्थ्य पत्र) साथ ही साथ पशु यूआईडी द्वारा पशुओं की पहचान और एक राष्ट्रीय डाटा बेस में पशुओं की पहचान को शामिल करना इस योजना के हिस्सा होंगे।
- इस योजना के तहत 8.5 करोड़ दुधारु पशुओं का पहचान की जाएगी और उनका डाटा इनाफ (INAPH) डाटा बेस में अपलोड कर दिया जाएगा।
- यह पशु रोगों की राकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के व्यापार में भी वृद्धि होगी।

## **b) ADVANCED BREEDING TECHNOLOGY**

- Assisted Reproductive Technique to improve availability of disease free female bovines through of sex sorted semen technology.
- Under the scheme 50 embryo transfer technology labs and In Vitro Fertilization labs care will be established.
- This will lead to exponential increase in milk production and productivity of animals in an exponential manner

## **c) NATIONAL BOVINE GENOMIC CENTER FOR INDIGENOUS BREEDS(NBGC-IB)**

- In developed dairy countries genomic selection is used to increase milk production and productivity for attaining faster genetic gain.
- In order to increase milk production and productivity of indigenous cattle, a National Bovine Genomic Centre will be established in the country.
- By using genomic selection indigenous breeds can be made viable within few generations.

## **(बी) उन्नत प्रजनन तकनीक**

- अस्सीस्टेड प्रजनन प्रौद्योगिकी के द्वारा मादा बोवाइन की संख्या में वृद्धि करना योजना का उद्देश्य है।
- यह लिंग सोरटेड बोवाइन वीर्य के उयोग से देश में किया जाएगा। यह तकनीक अभी केवल उन्नत डेयरी देशों में ही उपयोग में लायी जाती है। इससे केवल मादा बछड़ियों का ही उत्पादन होगा।
- इस के अंतर्गत 50 भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी के केंद्र/ इन विट्रो निषेचन (आईवीएफ) केंद्र भी खोले जाएंगे। जिससे दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि की जा सके।

## **(सी) राष्ट्रीय बोवाइन जेनॉमिक केंद्र—देशी नस्लों के लिए**

- विकसित डेयरी देशों में जेनॉमिक तकनीक का प्रयोग दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए किया जाता है।
- देश में देशी नस्लों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए देश राष्ट्रीय जीनोमिक केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- जेनॉमिक तकनीक के द्वारा कुछ ही वर्षों में देशी नस्लों को viable बनाया जा सकता है।

- This center will play crucial role in identification of disease free High genetic merit bulls.

#### **d) E-PASHUDHAN HAAT PORTAL**

- At present there is no authentic market for bovine germplasm in the form of semen, embryos, male & female calves; heifers and adult bovines. Farmers depend on middlemen for sale and purchase of quality germplasm.
- Breed wise information on availability of bovine germplasm is not available which is essential for promotion of indigenous bovine breeds.
- For the first time in the country under National Mission on Bovine Productivity E Pashudhan Haat portal has been developed. This portal will play important role in connecting breeders and farmers of indigenous breeds.
- Through this portal farmers will be aware about breed wise information on indigenous breeds. Farmers/breeders can sale animals of indigenous breeds through this portal. Information on all forms of germplasm has been uploaded on the portal. Immediately farmers can obtain benefits of the portal.
- This portal will give new dimensions to

- जेनॉमिक केंद्र रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

## **(डी) ई पशुधन हाट पोर्टल**

- वर्तमान में देश में उच्च गुणवत्ता-रोग मुक्त वाले जर्मप्लाज्म जैसे वीर्य; भ्रूण; बछड़े, बछड़ी और वयस्क पशुओं का कोई भी प्रामाणिक बाजार नहीं है। अच्छी नस्ल के पशुओं की खरीद के लिए किसानों को बिचौलियों पर निर्भर होना पड़ता है।
- पशुओं की नस्ल वार सूचना भी किसानों को उपलब्ध नहीं होती। जो की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन के अंतर्गत ई पशुधन हाट पोर्टल स्थापित किया गया है। यह पोर्टल देशी नस्लों के लिए प्रजनकों और किसानों को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इस पोर्टल के द्वारा किसानों को देशी नस्लों की नस्ल वार सूचना प्राप्त होगी। इससे किसान एवं प्रजनक देशी नस्ल की गाय एवं भैंसों को खरीद एवं बेच सकेंगे। देश में उपलब्ध जर्मप्लाज्म की सारी सूचना पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है। जिससे किसान इसका तुरंत लाभ उठा सके।
- इस तरह का पोर्टल विकसित डेयरी देशों में भी उपलब्ध

development and conservation of indigenous breeds as at present information on availability of germplasm of indigenous breeds is not available with the farmers.

- Through the portal there will be no involvement of middlemen in sale and purchase of animals. Portal for sale and purchase of germplasm in all the forms is not available even in developed dairy countries.

## **21. FISH PRODUCTION**

Fish production has increased from 186.12 lakh tonnes during 2012-14 to 209.59 tonnes during 2014-16 (an increase of Rs.12.61 %). The Annual growth rate of fish production during 2015-16 is 6.21%.

## **22. EGG PRODUCTION**

During the year 2015-16, 82,930 million eggs produced while during 2014-15, 78,484 million eggs were produced. Egg production is now increasing by 5.66% annually. In comparison to 2012-14 during 2014-16 egg production growth rate is 10.99 %. Annual egg production rate is 5 %. Per person availability of egg has reached 66.

नहीं है। इस पोर्टल के द्वारा देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि वर्तमान में किसानों के पास कोई नस्ल वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

- पोर्टल के माध्यम से जानवरों की खरीद और बिक्री में बिचौलियों की कोई भागीदारी नहीं होगी। जर्मप्लाज्म के सभी रूपों में बिक्री और खरीद के लिए इस तरह का पोर्टल विकसित डेयरी देशों में भी उपलब्ध नहीं है।

## 21. मछली उत्पादन

वर्ष 2012–14 के दौरान 186.12 लाख टन का उत्पादन हुआ जबकि 2014–16 के दौरान 209.59 लाख टन का उत्पादन हुआ जो कि 12.61 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2015–16 में मछली उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 6.21 प्रतिशत रही।

## 22. अंडा उत्पादन

2014–15 के दौरान 78484 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ व 2015–16 में 82930 मिलियन अंडों का उत्पादन हुआ जो कि 5.66 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष (2012–14) की अपेक्षा वर्ष (2014–16) में वृद्धि दर 10.99 प्रतिशत रही। अंडा उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिवर्ष 66 अंडे तक पहुंच गई है।

### **23. VETERINARY EDUCATION**

To ensure that the existing syllabus and standards for graduate veterinary education is aligned with globally accepted standards, wide-ranging amendments have been made in Minimum Standards for Veterinary Education Regulations, 2008. In addition to this, to meet the shortage of trained veterinary manpower, the number of veterinary colleges has increased from 36 to 46. Intake of students in various Veterinary Colleges was enhanced from 60 to upto 100 seats. Total number of seats has been increased to 1,334 from 914 in 17 Veterinary Colleges. The number of veterinary graduates has increased by one and half times. Similarly the seats in veterinary colleges have increased by one and half times. One and a half time increase in post graduate studies in veterinary education has been attained. Seats in veterinary colleges have been increased by one and a half time.

### **24. INCREASE IN RECRUITMENT OF SCIENTISTS**

81 % recruitment in 2014-15 and 2015-16 in comparison to only 66% in 2013-14, accelerated recruitment process through open competition and increase in representation of women scientists.



## 23. पशु चिकित्सा शिक्षा

मौजूदा स्नातक पशु चिकित्सा पाठ्यक्रम और मानकों को वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों अनुरूप के बनाने के लिए, पशु चिकित्सा न्यूनतम मानक विनियम, 2008 (Minimum Standards for Veterinary Education Regulations, 2008 ) में व्यापक संशोधन। साथ ही पशु चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षित पशु चिकित्सों की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 36 से 46 की गई है तथा कॉलेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को 60 से बढ़ाकर 100 तक किया गया था। 17 पशु चिकित्सा कॉलेजों में सीटों की कुल संख्या को 914 से बढ़ाकर 1,334 किया गया है। पशु चिकित्सा स्नातकोत्तर छात्रों में डेढ़ गुना की वृद्धि हासिल की गयी। पशु चिकित्सा विद्यालय में भी डेढ़ गुना सीटें बढ़ायी गयीं।

## 24. कृषि वैज्ञानिकों की भर्ती को बढ़ावा

वर्ष 2013-14 में 66 प्रतिशत भर्ती के मुकाबले 2014-15 व 2015-16 में लगातार 81 प्रतिशत भर्ती, खुली प्रतियोगिता से भर्ती प्रक्रिया को तेज किया गया व कृषि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ायी गयी।

## **25. EMPIRICAL LEARNING UNITS**

Compared to 2007-13, the number of empirical learning units in agricultural colleges was 362 which have now been increased to 426 in just two years during 2014-16 which is almost 18 percent increase. Education budget has also been increased by 50% in the last two years (2014-15 & 2015-16).

## **26. STRENGTHENING OF KVKs**

Efforts were made to strengthen the KVKs by enhancing the number of staff positions, providing facilities of soil testing, skill training and integrated farming system, etc.

## **27. ATTRACTING STUDENTS, YOUTH TOWARDS AGRICULTURE AND IMPROVING THE SCIENTISTS – FARMERS INTERFACE**

### **Attracting and Retaining Youth in Agriculture (ARYA)**

The ARYA project was implemented to empower the Youth in Rural Areas to take up various Agri-enterprises in Agriculture, allied and service sector for sustainable income and gainful employment. The project is running in 25 districts of 25 States through KVKs.

## 25. अनुभवजन्य लर्निंग इकाई

वर्ष 2007 से 2013 तक 6 वर्षों के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों में अनुभवजन्य लर्निंग इकाइयों की संख्या 362 थी जबकि वर्ष 2014 से 2016, दो वर्षों के दौरान 426 की गयी है जो कि 18 प्रतिशत की वृद्धि है। पिछले दो वर्षों (2014-15 एवं 2015-16) के शिक्षा बजट में भी 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

## 26. कृषि विज्ञान केन्द्रों का सुदृढीकरण

कृषि विज्ञान केन्द्रों को सुदृढ करने का कार्य प्रारंभ किया गया जिसके तहत प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में मिट्टी जांच की सुविधा, कौशल विकास को बढ़ावा, एकीकृत खेती प्रणाली, आदि की व्यवस्था के साथ-साथ कार्मिकों की संख्या को भी बढ़ाया गया।

## 27. कृषि में युवाओं, छात्रों को आकर्षित करना व वैज्ञानिकों और किसानों के इंटरफेस को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें

### आर्या

आर्या परियोजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कृषि संबंधी विभिन्न उद्यमों एवं सेवा क्षेत्र में सतत आय और लाभकारी रोजगार के लिए सशक्त और आकर्षित किया जाएगा। यह परियोजना कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 25 राज्यों के 25 जिलों में चलाई जा रही है। 5,000 युवाओं के लक्ष्य के साथ परियोजना का आरम्भ कर दिया गया है।

## **FARMER FIRST**

The Farmer FIRST aims at enriching Farmers – Scientist interface, technology assemblage, application and feedback, partnership and institution building and content mobilization. It provides a platform to farmers and scientists for creating linkages, capacity building, technology adaptation and application, on-site input management, feedback and institution building. The scientists from 100 ICAR Institutes/ Universities are expected to work with one lakh farmers directly.

## **STUDENT READY**

Introduction of Fellowship from 2016-17 @ Rs. 3,000 per month for all the students for a period of 6 months during Student Ready which was Rs. 750 per month earlier. Components of this scheme are:

- i. Experiential Learning (EL)
- ii. Rural Agriculture Work Experience (RAWEX)
- iii. In Plant Training /Industrial Attachment/ Internship
- iv. Skill Development Training
- v. Student Project

## फार्मर फस्ट

फार्मर फस्ट परियोजना का उद्देश्य किसान-वैज्ञानिक संवाद, प्रौद्योगिकी एकीकरण, तकनीकी प्रयोग और प्रमुख साझेदारी और संस्थागत विकास तथा परियोजना के अनुभवों को समृद्ध करना है। यह किसान और वैज्ञानिक के मध्य संबंध, क्षमता निर्माण, तकनीकी अनुकूलन तथा प्रयोग, ऑन साइट इनपुट प्रबंधन, संस्थागत निर्माण और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा 1 लाख किसानों के साथ सीधे तौर पर कार्य करने के लक्ष्य के साथ शुरुआत कर दी गई है।

## स्टूडेंट रेडी

वर्ष 2016-17 से अभ्येतावृत्ति के रूप में सभी छात्रों के लिए स्टूडेंट रेडी के दौरान 6 माह के लिए रु. 3000 प्रति माह मानदेय की शुरुआत जो पहले रु. 750 प्रति माह थी। इसके अंग इस प्रकार हैं-

- i. अनुभवजन्य अधिगम (ईएल)
- ii. ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (आरएडब्ल्यूई)
- iii. पौधा प्रशिक्षण/औद्योगिक जुड़ाव/प्रशिक्षण
- iii. कौशल विकास प्रशिक्षण
- iv. छात्र परियोजना

- **Mera Gaon- Mera Gaurav programme** has been initiated to effectively promote direct interface of scientists of ICAR Institutes and State Agricultural Universities with the farmers to hasten the lab to land process. For this, a group of four scientists each is adopting 5 villages. The project is intended to connect with 25,000 villages. At present, agricultural scientists have started providing information on newer technologies to the farmers in 10,712 villages.
- **Skill Development:** 100 KVKs have initiated training of youth in skill development related to agriculture and allied sectors. To stand with 4000 youths will be trained in two training programmes per KVKs

## **28. CLIMATE RESILIENT VARIETIES (DROUGHT RESISTANT AND FLOOD TOLERANT)**

During 2014 to 2016, 127 varieties of food grains, 70 of pulses, 58 of oilseeds and 37 of others (total 292 new varieties) have been developed.

- **मेरा गांव – मेरा गौरव योजना** को गांव तक वैज्ञानिक कृषि की प्रभावी तथा व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिकों को शामिल कर प्रारंभ किया गया है। इस उद्देश्य के लिए चार-चार वैज्ञानिकों के प्रत्येक समूह 5 गांवों को चयनित कर काम कर रहे हैं। इस योजना का लक्ष्य 25,000 गांवों को जोड़ना है। अभी तक 10,712 ग्रामों में कृषि वैज्ञानिक सम्पर्क कर नयी तकनीकी जानकारी देने का कार्य कर रहे हैं।
- **कौशल विकास :** 100 कृषि विज्ञान केंद्रों ने कृषि एवं संबंधित विषयों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु पहल की गई है। प्रारम्भिक दौर में 2 प्रशिक्षण प्रति केंद्र की दर से 4000 युवाओं का कौशल विकास करने एवं प्रमाण-पत्र देने का लक्ष्य है।

## 28. जलवायु सहिष्णु किस्में (सूखा प्रतिरोधी एवं बाढ़ सहनशील)

- वर्ष 2014 से 2016 तक अनाज की 127, दलहन की 70 एवं तिलहन की 58 तथा अन्य 37 किस्में (कुल 292 नयी किस्में) विकसित की गईं।

## 29. AGRICULTURE EDUCATION

- Recognizing the enormous potential of North-East India, six new colleges were opened by Modi government under Central Agricultural University, Imphal. Due to this, the number of agricultural colleges in the Northeast region has increased by almost 85 percent in the last two years.
- Similarly, in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh, 4 new colleges under Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University, Jhansi and conversion of Central Agriculture University have been completed.
- To make agriculture graduation courses income oriented, Government has approved the 5th Dean's Committee report recommendations of the committee. Dean's Committee report will be implemented in this educational session i.e. 2016-17. Through this new curriculum all agriculture based graduation courses will be altered into the professional ones which will be conducive to earn their livelihood in future



## 29. कृषि शिक्षा

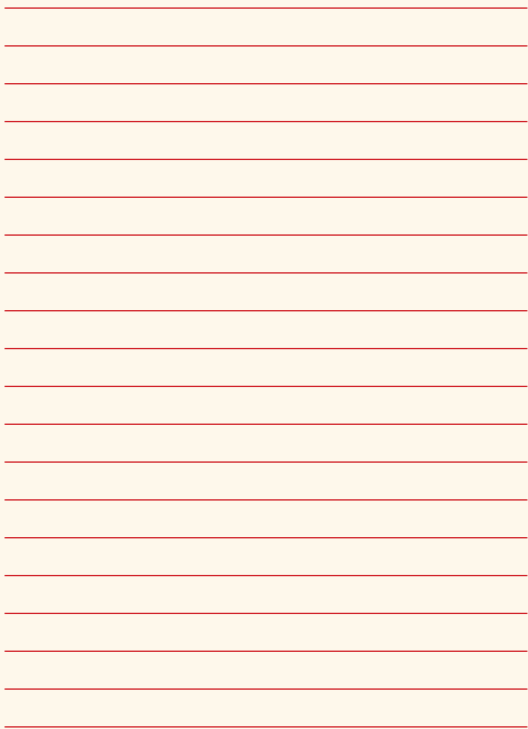
- पूर्वोत्तर भारत की अपार क्षमताओं को पहचानते हुए मोदी सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के अंतर्गत छः नए कॉलेज खोले गये। इससे पूर्वोत्तर भारत में कृषि कॉलेजों की संख्या में पिछले दो वर्षोंमें लगभग 85 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई।
- इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी तथा बिहार के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किए गये हैं।
- कृषि स्नातक पाठ्यक्रमों को व्यावसायिक बनाने के लिए, सरकार ने पाँचवी डीन्स कमेटी रिपोर्ट पर आधारित समिति के निर्देशों को अनुमोदित कर दिया है। डीन्स कमेटी रिपोर्ट को इसी वर्ष शिक्षा सत्र 2016–17 से लागू किया जाएगा। इस नये पाठ्यक्रम के माध्यम से कृषि आधारित समस्त स्नातक कोर्स प्रोफेशनल कोर्स की श्रेणी में तब्दील हो जाएंगे तथा कृषि स्नातकों को भविष्य में प्रोफेशनल कार्य से आजीविका पूर्ण करने में सहायक रहेंगे।

### 30. SPECIAL INITIATIVES

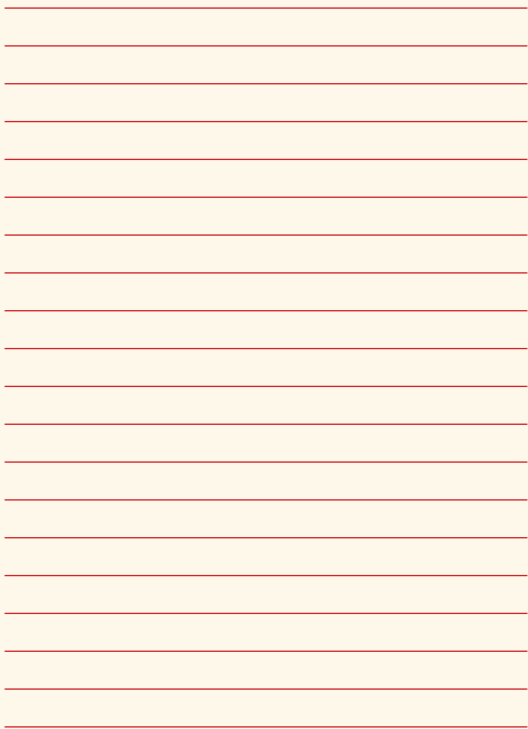
- Four new ICAR Awards in two years: ICAR Administrative award, Haldhar Organic Farmer Award, Pandit Deendayal Antyodaya Krishi Puruskar and Pandit Deendayal Rashtriya Krishi Vigyan Protsahan Puruskar.
- Pandit Deendayal Unnat Krishi Shiksha Yojana has been started in the year 2016 by way of 130 training programmes on organic farming/ natural farming and cow based economy in 32 SAUs of the country.
- Rashtriya Krishi Shiksha Divas is being celebrated on 3rd December in remembrance of country's first Agriculture Minister Dr. Rajendra Prasad.
- Jai Kisan-Jai Vigyan Week is being celebrated since the year 2015 across the entire country during 23rd to 29th December, on the occasion of birth anniversaries of Ch. Charan Singh and Shri Atal Bihari Vajpayee.
- Mahila Kisan Diwas will be celebrated on 15th October of each year to honour former women. The day will be celebrated with various programmes like agricultural exhibition, farmer women Goshati, etc.

## 30. विशेष पहल

- चार नए आईसीएआर पुरस्कार:
- आईसीएआर प्रशासनिक पुरस्कार
- हलधर आर्गेनिक किसान पुरस्कार
- पं० दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार
- पं० दीनदयाल राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार ।
- पं० दीनदयाल उन्नत कृषि शिक्षा योजना: देशभर के 32 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक खेती / प्राकृतिक खेती और गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर 130 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके वर्ष 2016 से शुरू की गयी है ।
- देश के प्रथम कृषि मंत्री, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की स्मृति में 3 दिसम्बर को **राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस** घोषित किया गया है ।
- चौधरी चरण सिंह और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर वर्ष 2015 से पूरे देश में दिसम्बर 23 से 29 के दौरान **जय किसान – जय विज्ञान सप्ताह** मनाया जा रहा है ।
- प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर **“महिला किसान दिवस”** के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है । इस अवसर पर कृषक महिलाओं को सम्मानित करने के साथ अन्य प्रकार के आयोजन जैसे संगोष्ठी, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जाएगा ।







# कृषि मुख्य दिवस

1. विश्व वानिकी दिवस	21 मार्च
2. विश्व पशु चिकित्सा दिवस	अप्रैल माह का अंतिम शनिवार
3. विश्व दुग्ध दिवस	1 जून
4. राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस	10 जुलाई
5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का स्थापना दिवस	16 जुलाई
6. विश्व शहद दिवस	20 अगस्त
7. विश्व नारियल दिवस	2 सितम्बर
8. विश्व अंडा दिवस	अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार
9. राष्ट्रीय महिला किसान दिवस	15 अक्टूबर
10. विश्व खाद्य दिवस	16 अक्टूबर
11. विश्व मात्स्यिकी दिवस	21 नवम्बर
12. राष्ट्रीय दुग्ध दिवस	26 नवम्बर
13. राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस	3 दिसम्बर
14. विश्व स्वायल दिवस	5 दिसम्बर
15. जय किसान जय विज्ञान सप्ताह	23-29 दिसम्बर



**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

भारत सरकार

[www.agriculture.gov.in](http://www.agriculture.gov.in)

सत्यमेव जयते